`` पुलिस की गश्तों के द्वारा और जो गलत प्रकार के लोग है उनके खिलाफ कार्यवाही करने के द्वारा और जिन-जिन एरियाज में अपराध ज्यादा है वहां पर पुलिस की हाई विजिबिलिटी हो इस माध्यम से और इम्प्रूव्ड इंटेलीजेंस के द्वारा जो कदम उठाए है उनका परिणाम आया है । लेकिन मैम मानूंग कि और कदम उठाने की जरूरत है । आपने इस कांड का उल्लेख किया कि जिसमेम कई लोग बीमार हो गए फूड पाइजनिंग था या कुछ और था –इसकी छानबीन हो रही है ।

श्रीमती वीणा वर्मा: सर, सेकेंड क्वेश्चन । खास तौर से महिलाओं के जो मामले है चाहे बलात्कार हो या इन पर कोई छीना-झपटी हो या उन पर कोई अत्याचार हो, मोलेस्टेशन हो तो उनमें यह देखा जाता है कि पहले तो एफ. आ.ई. आर. नहीं लिखी जाती है । महिला थाने खोलने के लिए भी आपका सुझाव था । सोनीपत, हरियाणा में बहुत से महिला थाने खोले गए थे पिछले समय । मैंने चार वर्ष पूर्व उसको उठाया भी था । 18 महिला थाने खोले गए । उनको एक तो ब्यूरोक्रेट्स और कुच कहिए कि प्रभावशाली लोगों और राजनीतिक, पुलिस ने मिलकर बंद करवाने की कोशिश की और वे बंद किए गए । उनमें काफी केसेज निपटाए गए थे, अच्छी तरह से जिम्मेदारी से निपटाए गए थे । तो क्या मंत्री जी पहले तो मुझे आश्वासन देंगे कि महिला थाने स्पेशली महिलाओं के द्वारा ही चले जहां एफ. आ.ई. आर. लिखवाई जा सकें? क्या उस पर जोर देंगे? उनको खुलवाने के सिवाय दूसरी चीज जो एन. सी, डब्ल्यूं, जो महिला कमीशन है क्या उसको यह पावर देने की भी आप सोचेंगे कि वहां पर जो रिपोर्ट दर्ज की जाए वह एफ. आ.ई. आर. समझी जाए?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महिला थानों का जो सुझाव है वह काफी समय से विचाराधीन रहा है । कई राज्यों में सफलतापूर्वक क्रियान्वित हुआ है । दिल्ली में कुच साल पहले प्रयोग हुआ । वह सफल नहीं हुआ । लेकिन फिर भी मैंने अपने पुलिस अधिकारीयों को कहा कि इस पर फिर से विचार करना चाहिए । उनका कहना यह है कि दिल्ली में सफल नहीं हुआ है .....(**व्यवधान**)

श्रीमती वीणा वर्मा: उसमें तो सफलता रही है ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: लेकिन इस पर जरूर विचार करेंगे । कुल मिलाकर के भी यहां निर्णय हुआ है कि 17 और नये थाने खोले जाए और वैसे साधारणतया बहुत समय लगता है लेकिन मैं आशा करता हूं कि 31 जनवरी, 199 के महीने तक ये आपरेशनल हो जाएंगे।

MR. CHAIRMAN: Question No. 58, on the same subject. Shri K.K. Birla. Do you want to put a question? *(Interruptions).*

श्रीमती वीणा वर्मा : महिला थाने और एन.सी.डब्ल्यू. ए. – नेशनल कमीशन फार वीमेन में जो एफ.आई.आर. लिखी जाए या जो एप्लीकेशन दर्ज हो वह एफ.आई.आर. मानी जाए इसके बारे में बताएं ।

श्री लाल कृष्णआडवाणी : महिला आयोग के अपने अधिकार हैं और उनमें कोई बढ़ोतरी का कंक्रीट प्रस्ताव आएगा तो जरूर विचार करेंगे ।

SHRIMATI JAYANTHI NATRA-JAN: First, appoint a Chairman for the National Commission for Women.

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय : सभापित महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से केवल यह कहना चाहूंगी कि जो आंकड़े आपने दिए हैं उन आकडों में आपने कहा है।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Proposal to Construct A Hotel at Borra Caves

*45. SHRI SOLIPETA RAMA CHANDRA REDDY: Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) whether Borra caves near Araku valley in Vizag District in Andhra Pradesh are unique in our country;

(b) whether I.T.D.C. has any proposal to construct a hotel for the convenience of middle class tourists in that area;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF TOURISM (SHRI MADAL LAL KHURANA): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) I.T.D.C.'s Annual Plan 1998-99 docs not include any proposal for the construction of a Hotel in the Vizag area. Accommodation for the convenience of middle class tourists are available in and around the area.

सेना में अधिकारियों के रिक्त पद

*46 **श्री डी.पी. यादव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेना में अधिकारियों के कुल कितने पद इस समय रिक्त हैं,

(ख) क्या यह सच है कि सेना में अधिकारियों की कमी से सेना का मनोबल गिरा है, और

(ग) क्या सरकार ने अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने हेतु कोई कार्रवाई की है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडिस) : (क) से (ग) इस समय सेना में 13,271 अफसरों की कमी है। तथापि, अफसरों की कमी होना नई बात नहीं है। विगत में भी यह कमी अलग-अलग स्तरों पर नहीं है। अफसरों की कमी से सेना के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

सेना में अफसर संवर्ग में कमी पूरी किए जाने के लिए विभिन्न उपाय शुरू किए गए हैं, यथा विश्वविद्यालय प्रवेश योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर के "ग" प्रमाण-पत्र धारकों को अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अफसर के रूप में भर्ती किए जाने के लिए उन्हें सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा में बैठने से छूट देना महिलाओं की अफसरों के रूप में भर्ती, सेवारत जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों/अन्य रैंकों को विशेष कमीशन प्राप्त अफसर संवर्ग में पदोन्नति देना और 10+2 तकनीकी प्रवेश योजना शुरू करना।

एक व्यावसायिक विज्ञापन एजेंसी की सहायता से 1997-98 के दौरान सेना की छवि-प्रदर्शन का अभियान चलाया गया था। इस दिशा में हुई उपलब्धियों को और समेकित करने के लिए सरकार ने इस अभियान का चरण – II शुरू करने का निर्णय लिया है।

सरकार ने सशस्त्र सेना कार्मिकों के लिए पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों में और सुधार करते हुए उन्हें लागू कर दिया है।

यह आशा है कि इन सभी प्रयायों में समवेत प्रभाव के फलस्वरूप भर्ती में वृद्धि होगी, जिससे निकट भविष्य में अफसरों की कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी।

Action Plan to fight insurgency in North-East

*47. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have since prepared an Action Plan to fight increasing insurgency in North-East region;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (c) Insurgency in trite North East has never been looked upon only as a law and order problem. The development and deepening of democratic processes has been the basic framework within which the problems of the North-East have been approached. Development strategy since Independence has been pursued within the broad framework of planning with a view to ensure that people develop along the lines of their own genius and nothing should be imposed on them and that traditional way of life and culture are encouraged. The efforts should be to train and build indigenous teams to do the work of administration and development and that development should come through indigenous social and cultural institutions.

The strategy to curb insurgency includes a willingness to meet and discuss legitimate grievances; resolve that violence would not be tolerated; friendly relations with neighbouring countries; accelerated infrastructural development; stress on employment schemes; and good governance and decentralisation.

The State Governments have formulated their own Action Plans to fight insurgency. The Union Government monitors, cordinates and reinforces these Plans. The steps taken by the Central